भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

10.03.2021 के

अतारांकित प्रश्न सं. 2721 का उत्तर

उर्वरक रेक प्वाइंट

2721. श्री सुब्रत पाठक:
श्री रविन्दर कुशवाहा:
श्री रवि किशन:
श्री बिद्युत बरन महतो:
श्री चंद्र शेखर साहू:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री राजेन्द्र धेड्या गावित:
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:
श्री सुधीर गुप्ता:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उन उर्वरक रेक प्वाइंटों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जहां देश के विभिन्न हिस्सों में प्लेटफॉर्म, कवर शेड, बिजली, ट्रकों हेतु संपर्क सड़क जैसी सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष ऐसे बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए आवंटित, जारी और उपयोग की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेक प्वाइंटों की अनुपलब्धता और खराब अवसंरचना के कारण उर्वरकों की आपूर्ति और उसका वितरण प्रभावित हुआ है और यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) 2021-22 में बनाये जाने वाले प्रस्तावित रेक प्वाइंटों का राज्य-वार विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र ओडिशा और झारखंड के संबंध में ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, वाणिज्य एवं उद्योग और
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) : देशभर में भारतीय रेल पर वितरित किए गए 926 से अधिक रेक पॉइन्ट हैं जिनके पास उर्वरकों की सम्हलाई हेतु आवश्यक अवसंरचना हैं। उर्वरक रेक पॉइन्टों के राज्य-वार वितरण को दर्शाने वाली सूची परिशिष्ट-I के रूप में संलग्न है।

(ख) देशभर में मौजूदा उर्वरक रेक पॉइन्टों पर अवसंरचना के सृजन अथवा सुदृढ़ीकरण, संसाधनों की उपलब्धता के साथ-साथ परिचालनिक और तकनीकी व्यवहार्यता के आधार पर आवश्यकता आधारित एक सतत प्रक्रिया है। अवसंरचना के सृजन हेतु, बजट में विशिष्ट कार्यों को स्वीकृति दी जाती है और भारतीय रेल के वार्षिक पूंजीगत व्यय के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है। पिछले तीन वर्षों में, 1975 करोड़ रूपए की लागत पर बजट में ऐसे 60 कार्यों की स्वीकृति के द्वारा विभिन्न रेक पॉइन्टों पर अवसंरचना का सृजन किया गया है। विगत तीन वर्षों में आबंटित, जारी की गई और उपयोग में लाई गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा, परिशिष्ट-II के रूप में संलग्न है। सामान्यतः वित्त वर्ष के आरंभ में आबंटन किए जाते हैं, जिसमें परिवर्तन किया जा सकता है और कार्य की प्राथमिकता के आधार पर एक योजना शीर्ष से दूसरे योजना शीर्ष में निधियों के पुनर्विनियोग की स्थापित प्रणाली मौजूद है। पिछले तीन वर्षों में अवसंरचना के सृजन में व्यय की गई धनराशि, विगत तीन वर्षों में आबंटन की तुलना में काफी अधिक है, जो यह दर्शाता है कि भारतीय रेल द्वारा अवसंरचना के सृजन और अपने माल टर्मिनलों के विकास को उच्च प्राथमिकता दी जाती है।

(ग) जी नहीं। भारतीय रेल द्वारा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय की आवश्यकता के अनुसार उर्वरकों का परिवहन किया जाता है। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय से रेक पॉइन्टों पर गैर-उपलब्धता और कमजोर अवसंरचना के कारण उर्वरकों की आपूर्ति और इसका वितरण प्रभावित होने से संबंधित कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) वर्ष 2021-2022 के लिए रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय से जब भी नए रेक पॉइन्टों हेतु प्रस्ताव प्राप्त होता है, इस पर रेल मंत्रालय द्वारा परिचालनिक एवं तकनीकी व्यवहार्यता के आधार पर विचार किया जाएगा।

*****

भारतीय राष्ट्रीय रेल योजना-2019 के संबंध में दिनांक 10.03.2021 को लोक सभा में श्री सुब्रत पाठक, श्री रविन्दर कुशवाहा, श्री रवि किशन, श्री बिद्युत बरन महतो, श्री चंद्र शेखर साहू, श्री श्रीरग आप्पा बारणे, श्री राजेन्द्र धेड्या गावित, श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक, और श्री सुधीर गुप्ता के अतारांकित प्रश्न सं. 2721 के भाग (क) के उत्तर से संबंधित परिशिष्ट-I

(क) उर्वरकों के रेक पॉइन्टों के राज्य/ संघ शासित प्रदेश वार वितरण

राज्य/ संघ शासित प्रदेश का नाम	उर्वरकों के रेक पॉइन्टों की संख्या
आंध्र प्रदेश	46
असम	33
बिहार	55
चंडीगढ़	1
छत्तीसगढ़	30
दादर और नागर हवेली	3
दमन एवं दीव	2
गोवा	1
गुजरात	38
हरियाणा	35
हिमाचल प्रदेश	6
जम्मू एवं कश्मीर	23
झारखंड	17
कर्नाटक	42
केरल	20
मध्य प्रदेश	74
महाराष्ट्र	89
मणिपुर	1
मिजोरम	1
नागालैंड	1
ओडिशा	37
पुदुचेरी	1
पंजाब	56
राजस्थान	68
तमिलनाडू	35
तेलंगाना	24
त्रिपुरा	3
उत्तर प्रदेश	128
उत्तराखंड	11
पश्चिम बंगाल	45
कुल योग	926

भारतीय राष्ट्रीय रेल योजना-2019 के संबंध में दिनांक 10.03.2021 को लोक सभा में श्री सुब्रत पाठक, श्री रविन्दर कुशवाहा, श्री रवि किशन, श्री बिद्युत बरन महतो, श्री चंद्र शेखर साहू, श्री श्रीरग आप्पा बारणे, श्री राजेन्द्र धेड्या गावित, श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक, और श्री सुधीर गुप्ता के अतारांकित प्रश्न सं. 2721 के भाग (ख) के उत्तर से संबंधित परिशिष्ट-।।

(ख) पिछले वर्षों में भारतीय रेल पर चालू 60 माल शेड/माल टर्मिनल की वित्तीय स्थिति

क्र.सं.	राज्य	कार्यों की सं.	लागत (करोड़ रु. में)	ब.अ (2018-19) के अनुसार आबंटन (करोड़ रु. में)	2018-19 में वास्तविक व्यय (करोड़ रु. में)	ब.अ (2019-20) के अनुसार आबंटन (करोड़ रु. में)	2019-20 में वास्तविक व्यय (करोड़ रु. में)	ब.अ (2020-21) के अनुसार आबंटन (करोड़ रु. में)	2020-21 में वास्तविक व्यय (करोड़ रु. में)
1	असम	2.000	43.280	7.680	7.680	2.560	2.560	5.700	2.400
2	बिहार	10.000	121.110	24.001	38.371	4.615	39.966	11.205	44.880
3	छत्तीसगढ़	2.000	13.000	0.260	0.280	0.000	0.000	0.000	0.000
4	दिल्ली	1.000	225.590	2.000	8.710	46.580	6.960	1.800	4.700
5	गुजरात	4.000	24.290	5.720	4.160	1.500	2.360	0.540	0.710
6	हरियाणा	2.000	805.450	3.000	0.000	0.000	450.000	0.000	0.000
7	जे. एवं के.	1.000	18.520	0.500	18.520	0.000	0.000	0.500	0.000
8	झारखंड	3.000	23.280	3.640	1.985	8.000	3.475	2.460	2.709
9	कर्नाटक	1.000	4.570	0.000	1.540	0.100	0.500	5.000	0.000
10	केरल	1.000	5.440	0.000	0.098	0.000	0.516	0.000	0.304
11	मध्य प्रदेश	5.000	90.570	2.470	52.480	8.900	63.130	6.560	63.840
12	महाराष्ट्र	3.000	22.500	1.023	1.384	0.002	0.240	0.001	0.004
13	ओडिशा	9.000	93.960	5.711	10.380	8.289	5.375	1.647	3.301
14	पंजाब	1.000	9.110	0.001	1.750	0.560	6.500	2.500	0.000
15	राजस्थान	1.000	8.000	0.450	0.560	0.000	0.000	8.400	0.070
16	तमिलनाडू	2.000	12.650	2.020	0.700	0.505	0.000	0.000	0.000
17	उत्तर प्रदेश	5.000	244.330	1.990	16.340	6.100	21.750	1.500	27.420
18	उत्तराखंड	2.000	12.750	1.351	1.149	0.387	0.000	0.300	0.470
19	पश्चिम बंगाल	4.000	165.850	70.500	23.418	24.632	30.374	32.710	24.825
20	ओडिशा, आंध्र प्रदेश एवं छत्तीसगढ़	1.000	30.800	4.000	6.680	2.500	1.020	1.600	0.050
	कुल	60	1975	136	196	115	635	82	176

*****